Setting up an Ammonia Plant Krishna-Godavari Basin

746. SHRI SURESH KALMADI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state·

(a) whether it is a fact that Government have decided to go ahead with its plans to set up a 450 tpd ammonia plant in the Krishna-Godavari basin despite poor prospects of gas allocations for the project; and

(b) if so, by when the award of the project is likely to be finalised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) and (b) Indications are available regarding availability of 0.50 million cubic metre per day of gas for setting up of one 450 TPD ammonia and 800 TPD urea plant in the Krishna-Godavari Basin. However, no final decision has been taken by the Government regarding award of the project to a particular company.

747. [*Transferred to the 21st July, 1992*].

Ignoring highest import price

748. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1142 given in the Rajya Sabha on the 7th May, 1992 and state:

(a) whether it is a fact that a decision was taken in his Ministry in 1990 to ignore the highest import price to prevent overinvoicing of imports;

(b) if so, what were the drugs involved and what was the import price on which the formulation prices were based;

(c) when was the decision reversed and is it a fact that the decison taken at the level of then Minister was reversed at the level of Development Commissioner; and

(d) whether it is a fact that the benefit of crores of rupees have been given to certain multinationals and if so, what steps have been taken to investigate the matter and fix responsibility?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) and (b) No general decision of this kind was taken. However, in case of one drug *viz.*, Hyoscine-N-Butyl Bromide instead of the weighted average price, a lower price was adopted on the basis of data available in the Department.

(c) annd (d) Do not arise.

Submitting data by drug company

749. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU. Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1134 given in Rajya Sabha on 7th May, 92 and orders;

(a) what were the time schedules laid down by the Bombay High Court for getting data and passing the orders;

(b) what changes have been made in the data submitted by the company to special team, and as verified by this team; and

(c) what is the present status of the case and what are the details of development during the last one year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) The Bombay High Court in its Order dated 8th March, 1991 allowed two weeks for amendment of petition, 8 weeks to M/s, Hoechst for giving data to the Government, 4 weeks to the Government to furnish particulars to the company consistent with the judgement of the Suprema Court in Cyanamid's case, 8 weeks to the Government to determine tentative liability, if any, due from the company and 4 weeks to the Government to give hearing to the company and pass speaking order.

(b) The question is not clear.

(c) the Government's is directing the company to submit the complete data, however the company is trying to avoid the same on one pretext or the other. The Government has given a final opportunity to the company to submit the data. In case full data is not given by the company whatever data becomes available to the Government from whichever source, will be made use of to supplement the company's date. After the liability has been tentatively determined, in this way, the company will be given a hearing in accordance with the Bombay High Court's order and a speaking order will be passed thereafter.

कमजोरवर्गों को खाद्यानों का वितरण

750. **श्री विश्वास राव रामराव पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यनों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए समाज के उस वर्ग का पता लगाने का विचार रखती है जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को इस सबध में प्राथमिकता मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में सरकार के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न वस्तुऐ घटिया किस्म की होती है और इन वस्तुओं की सप्लाई अनियमित है ; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने की विचार है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालूद्दीन अहमद) : (क) और (ख) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्वरूप सर्वव्यापी है और इसमें आय या व्यवसाय आदि के आधार पर लाभान्वितों के बीच अंतर नहीं किया जाता है । लेकिन दूर-दराज, पहाड़ी, दूरस्थ, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अधिकांशत: गरीब लोग रहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा बेहतर तरीके से पहुचाने के लिए केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से उन क्षेत्रों का चयन किया है जो विभिन्न क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल, विकास कार्यक्रम समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं तथा विनिर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के अतर्गत आते हैं । इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहू व चावल विशेष रूप से राजसहायतायुक्त मूल्यों पर दिए जाते हैं जो सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों से कम होते हैं । जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा कम है वहां अतिरिक्त उचित दर की दुकानों खोलने जिन लोगों के पास अब तक राशन कार्ड नहीं हैं उन्हें अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करने तथा भडारण क्षमता सृजित करने के लिए कार्यवाही की गई है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे मा.उचित दर दुकानों के स्तर पर सतर्कतासमिति गठित करे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की दरवाजे पर सुपुर्दगी का व्यवस्था करे ।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु निर्धारित मानकों तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की अपेक्षाओं के अतर्गत आ वाले खाद्यान्न जारी किए जाते हैं । वितरित की जाने वाली अन्य वस्तुयें भी निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप होती हैं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे कदाचारों को रोकने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के अन्यत्र भेजे जाने को रोकने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री के जरिए वितरित की जाने वाली वस्तुओं की गुणता की जांच करने के लिए उचित दर की दूकानों के निरीक्षण कार्य में तेजी जलायें ।